[2009] 13 (अतिरिक्त) एस.सी.आर. 589

राजस्थान राज्य

बनाम

नरेश @ राम नरेश

(आपराधिक अपील संख्या 837/ 2002)

26 अगस्त 2009

[न्यायमूर्तिगण दलवीर भंडारी और डॉ. मुकुंदकम शर्मा]

दंड संहिता, 1860 - उपधारा 302 और 394 - हत्या - महिला की हत्या और उसके गहने छीन लिए गए - मृतक के दोनों पैर काट दिए गए - अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था - ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि - उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति - चुनौती - आयोजित: साक्ष्य अभियुक्तों द्वारा खेत में अपराध करने और मृतक के

पैर काटने के संबंध में न तो ठोस और न ही विश्वसनीय - आभूषणों की बरामदगी पूरी तरह से रहस्य में डूबी हुई है - अपराध के कथित हथियार खुले स्थान से बरामद हुए हैं और उनमें खून के धब्बे नहीं हैं - उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृश्य प्रशंसनीय है इसलिए, लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए न कि अभियोजन पक्ष को - ऐसा मामला नहीं जहां दिए गए साक्ष्य विश्वसनीय हों और निर्णायक रूप से स्थापित हों कि अभियुक्त ने केवल अपराध किया है - मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है - अपील - बरी किए जाने के विरुद्ध - हस्तक्षेप की गुंजाइश - साक्ष्य - परिस्थितिजन्य साक्ष्य - की सराहना।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रतिवादी आरोपी ने एक महिला की हत्या कर दी और उसके गहने छीन लिये। यह आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी ने "खुरपी" का उपयोग करके मृतक के दोनों पैरों को काट दिया और पैरों की एक जोड़ी चांदी की पायल, हाथों की एक जोड़ी चांदी की कंगन, एक

जोड़ी चांदी की कान की बाली और एक सोने की नथुनी छीन ली। नाथ).

अभियोजन का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर टिका था.

ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर माना कि अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित चार प्रकार के परिस्थितिजन्य साक्ष्य पेश किए: (i) आरोपी बी मृतक की हस्तरेखा के माध्यम से हथेली की जांच कर रहा था और मृतक खेत की ओर चला गया; (ii) अभियुक्त भी खेत की ओर चला गया; (iii) आरोपी ने अपराध करने के बाद अपने हाथ धोए और मृतक का खून खेत में पाया गया और (iv) आरोपी मिट्टी से सना हुआ खेत से लौटा, उसके हाथ में "पोटली" थी, उसे जाते हुए देखा गया गांव से तथा आरोपी की पहचान होने पर मृतका के आभूषण, जो उसके शरीर से पैर काटकर निकाल लिये गये थे, वही डी जब्त किये गये तथा आभूषण-वस्तुओं की पहचान की कार्यवाही की गयी। ट्रायल कोर्ट ने माना कि उपरोक्त परिस्थितियां साबित करती हैं और स्थापित करती हैं कि प्रतिवादी ने अपराध किया था और उसे आईपीसी की धारा 302 और 394

के तहत दोषी ठहराया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था और किसी भी परिस्थिति से यह निष्कर्ष नहीं निकला कि प्रतिवादी ने कथित अपराध किया था। इसलिए वर्तमान अपील।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

अभिनिर्धारित किया: 1. बरी करने के आदेश में हल्के से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, भले ही अदालत का मानना हो कि कुछ सबूत हैं जो आरोपी की ओर इशारा कर रहे हैं। [पैरा 18]

अनिल कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2004) 13 एससीसी 257*; चंद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य,* (2007) 4 एससीसी 415 *और यूपी राज्य बनाम गंभीर सिंह* (2005) 11 एससीसी 271, संदर्भित।

2.1. वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया उनमें से कोई भी प्रतिवादी के खिलाफ साबित नहीं हुई,

जिससे यह निश्चित निष्कर्ष निकला कि यह वही था, जिसने अपराध किया था। साक्ष्यों से पता चला कि मृतक दिनांक 12.08.1993 को लगभग 3 बजे खेत की ओर गया था तथा अभियुक्त भी हाथ में लोटा लेकर खेत की ओर गया था। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा बयान पुलिस के सामने नहीं दिया गया था और उच्च न्यायालय ने इसे सुधार के रूप में पाया और फैसले में दर्ज किया। पीडब्लू-4 ने अपने बयान में कहा है कि वह मवेशियों को चारा देने के लिए "कोठी" पर गई थी। उसने यह भी कहा है कि जब वह मवेशियों को पानी पिलाने के लिए खेत में बैठी थी, तो उसने देखा कि आरोपी गांव की ओर भाग रहा था और आरोपी के साथ एक "*गद्दी*" और एक "*गांव*" भी था। अपनी जिरह में उसने कहा कि उसने आरोपी को "खेली" पर बैठे देखा था और उसने आरोपी की ओर पीठ कर ली थी क्योंकि आरोपी अपने हाथ धो रहा था। यदि वह गवाह घटना स्थल के निकट खेत में मौजूद थी, तो ऐसा कोई अवसर नहीं था कि उसने कथित वास्तविक घटना को क्यों नहीं देखा होता। यदि आरोपी ने

अपराध किया है तो उसे घटना स्थल पर बहुत लंबे समय तक रुकना पड़ा होगा क्योंकि आरोप है कि आरोपी ने मृतक के पैर काट दिए थे और पैरों की एक जोड़ी चांदी की पायल, हाथों की एक जोड़ी चांदी की कंगन, कथित तौर पर एक जोड़ी चांदी की बालियां और एक सोने की नाक की अंगूठी (नथ) ले ली गई। जब आरोप "खुरपी" के उपयोग से दोनों पैरों को काटने का है, तो इसमें काफी समय लगा होगा, जिसके दौरान उक्त गवाह पीडब्लू-4 ने घटना को स्वयं देखा होगा। पीडब्लू4 की ओर से भी इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि जब उसने आरोपी को हाथ धोते देखा तो उसने अपनी पीठ क्यों मोड़ ली। वह यह नहीं बताती कि उसने मृतक को आरोपी के साथ देखा था और न ही यह बताती है कि उसने आरोपी को कीचड़ से सना हुआ देखा था। [पैरा 19]

2.2. किसी भी गवाह की ओर से एक भी बयान नहीं आया कि उन्होंने किसी पानी को मृतक के खून से सना हुआ देखा हो या किसी खेत की मिट्टी को इंसान के खून से सना हुआ देखा हो। कुछ गवाहों ने कहा है

कि जब आरोपी खेत से लौट रहा था तो उस पर कीचड़ लगा हुआ था जबकि पीडब्लू-4 ऐसा नहीं कहता है। वह केवल इतना कहती है कि उसने उसे खेतों से भागते हुए देखा था। यह भी ज्ञात नहीं है कि उक्त गवाह ने केवल इसलिए अभियुक्त की ओर पीठ क्यों कर ली क्योंकि अभियुक्त अपने हाथ धो रहा था। यदि अभियुक्त अपने हाथ धो रहा था, जैसा कि पीडब्लू-4 ने कहा है, तो अभियुक्त के शरीर पर कीचड़ लगे होने की कोई संभावना नहीं है, जैसा कि अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों (पीडब्लू 7 और 8) ने आरोप लगाया है। [पैरा 20]

2.3. ट्रायल कोर्ट ने भी आरोपी को दोषी ठहराया क्योंकि मृतक के शव के पास कलाई घड़ी का पट्टा पाया गया था, जो कथित तौर पर आरोपी का था। सबूतों की जांच करने पर इस अदालत को ऐसा कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिला कि कलाई घड़ी का उक्त पट्टा अभियुक्त की घड़ी का है। किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा कि कलाई घड़ी का ऐसा पट्टा अभियुक्त का है और न ही अभियुक्त के पास से कोई कलाई घड़ी बरामद हुई है।

जहां तक घटना के समय का सवाल है, वहां भी कोई एकमत नहीं है और घटना के समय के संबंध में साक्ष्य कम हैं। • इस न्यायालय की सुविचारित राय में, अभियुक्त द्वारा क्षेत्र में अपराध करने और पैरों के विच्छेदन के संबंध में भी साक्ष्य हैं। मृतक की स्थिति न तो ठोस है और न ही विश्वसनीय है, और इसलिए, प्रतिवादी की सजा के आधार के लिए उन परिस्थितियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। [पैरा 21]

2.4. जहां तक आभूषणों की बरामदगी की बात है तो उस संबंध में मुख्य गवाह पीडब्लू-20 है। उक्त आभूषण आरोपियों की निशानदेही पर पीडब्लू-20 की हिरासत और कब्जे से बरामद किए गए। पीडब्लू-20 ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा था कि आरोपी उसके पास यह कहकर आया था कि वह अपने घर के गहने बेचना चाहता है। हालाँकि, उक्त गवाह ने कहा कि उन्होंने ऐसे आभूषण नहीं खरीदे, जिन्हें बाद में उनसे जब्त कर लिया गया। उन्होंने जिरह में बताया कि वे पुराने गहनों से नये गहने बनाने का कारोबार करते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उक्त आभूषण उनके

उपयोग के लिए नहीं थे और इसलिए उन्होंने खरीदने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी खुद सुनार है इसलिए वह पहले भी उसके पास आता था। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी ने उनसे गहने रखने के लिए कहा और कहा कि वह जल्द ही वापस आएंगे, और इसलिए, उन्होंने उक्त गहने रख लिए और उसी दिन आरोपी ने उनके गहने छीन लिए। यदि आरोपी ने उसी दिन आभूषण छीन लिए तो पुलिस पीडब्लू-20 की हिरासत और कब्जे से वही आभूषण कैसे बरामद कर सकी। इसके अलावा, चूंकि उसने कहा था कि वह आभूषण नहीं खरीदेगा, इसलिए आरोपी के पास उस आभूषण को पीडब्लू-20 के पास रखने का कोई अवसर नहीं था। प्रकटीकरण बयानों में आरोपी ने कहा कि उसने आभूषण राम चंद्र सराफ को बेचे थे जबकि उसे पीडब्लू-20 से बरामद किया गया था। सबूतों की जांच करने पर, यह पाया गया कि आभूषणों की उपरोक्त बरामदगी पूरी तरह से रहस्य में डूबी हुई है क्योंकि यह उस स्थान और

व्यक्ति से बरामद नहीं किया गया था, जिसे कथित तौर पर आरोपियों ने बेचा था। [पैरा 22]

2.5. जहां तक "खुरपी" की बरामदगी का सवाल है तो उसने माना कि उस पर कोई खून का धब्बा नहीं था और उसे एक खुले स्थान से बरामद किया गया था। चूंकि उस पर कोई खून का धब्बा नहीं था, इसलिए पुलिस ने उसे रासायनिक जांच के लिए भी नहीं भेजा. अत: यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त हथियार का प्रयोग मृतक की हत्या करने में किया गया था। घटना के समय आरोपी के आचरण के संबंध में कुछ संदेह हो सकता है लेकिन यह किसी भी तरह से निर्णायक रूप से साबित या स्थापित नहीं हो सकता है कि आरोपी ने मृतक की हत्या की है। जब तक साक्ष्य स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से अभियुक्त के अपराध को स्थापित नहीं करते, तब तक बरी करने के आदेश को रद्द करके दोषसिद्धि का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। [पैरा 23]

3. उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण पाया गया है, और इसलिए, लाभ हमेशा अभियुक्त को जाना चाहिए, न कि अभियोजन पक्ष को। यदि अभियोजन पक्ष तथ्य को साबित करना चाहता है, तो इसे प्रमुख साक्ष्यों से साबित किया जाना चाहिए, जो विश्वसनीय और भरोसेमंद हो, जो अभियुक्त के अपराध को इंगित करता हो और निर्णायक रूप से साबित करता हो। यह ऐसा मामला नहीं है जहां कोई सुरक्षित रूप से यह मान सके कि पेश किए गए सबूत भरोसेमंद थे और निर्णायक रूप से यह स्थापित करते हैं कि यह केवल आरोपी है, जिसने अपराध किया था। मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है। [पैरा 24]

केस कानून संदर्भ:

(2004) 13 एससीसी 257 करने के लिए भेजा पैरा 18

(2001) 4 एससीसी 415 करने के लिए भेजा पैरा 18

(2005) 11 एससीसी 271 करने के लिए भेजा पैरा 18

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2002 की आपराधिक अपील संख्या 837

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर के दिनांक 18.7.2001 के निर्णय एवं आदेश से डी.बी. 1996 की आपराधिक जेल अपील संख्या 331

अपीलकर्ता की ओर से मिलिंद कुमार।

प्रतिवादी की ओर से के. सारदा देवी।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

डॉ. मुकुंदकम शर्मा, जे. 1. यह आपराधिक अपील राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 18.07.2001 को पारित फैसले और आदेश से व्यथित होकर राजस्थान राज्य द्वारा दायर की गई है, जिसमें प्रतिवादी - आरोपी

को भारतीय धारा 302 और 394 के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया है। दंड संहिता (इसके बाद इसे "आईपीसी" कहा जाएगा)। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट द्वारा अभियुक्त के खिलाफ पारित फैसले और सजा के आदेश को रद्द करते हुए प्रतिवादी को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

2. पार्टियों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर चर्चा करने से पहले, आईपीसी की धारा 302 और 394 के तहत प्रतिवादी के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कुछ तथ्य निर्धारित करना आवश्यक होगा।

12.08.1993 को खुशाल सिंह (पीडब्लू-21), जो तत्कालीन एस.एच.ओ. थे। पुलिस थाना बस्सी को वायरलेस पर सूचना मिली कि किसी ने एक महिला की हत्या कर तथा पैर भी काट कर उसकी चांदी की पायल छीन ली है तथा उसका शव गांव कुठड़ा के पास पड़ा हुआ है। उपरोक्त सूचना मिलने पर, थाना प्रभारी पुलिस दल के साथ गांव कुथाड़ा पहुंचे, जहां सीता राम पुत्र भगवान सहाय ने एक लिखित रिपोर्ट, प्रदर्शनी पी-7 प्रस्तुत की,

जिस पर उन्होंने समर्थन किया। उपरोक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने एफआईआर संख्या 302/1993 आईपीसी की धारा 302 और 394 के तहत मामला दर्ज किया। दिनांक 13.08.2001 को उक्त मामला दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान प्रारम्भ किया।

3. जांच के दौरान, पीडब्लू-21 ने मृतक गुली देवी की एक जांच रिपोर्ट तैयार की, जिसे प्रदर्शनी पी-8 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। सुमेर सिंह (पीडब्लू-19), सर्कल अधिकारी ने 13.08.1993 को साइट का निरीक्षण किया और साइट योजना तैयार की। उन्होंने मृतक के खून से सने कपड़े, खून से सनी मिट्टी, खेली के फर्श का एक सीमेंट का टुकड़ा, जिस पर खून के धब्बे थे, कलाई घड़ी का एक पट्टा - प्रदर्शनी पी-5, एक लाठी और एक जोड़ी जूते - प्रदर्शनी पी-6 को भी अपने कब्जे में ले लिया। . उन्होंने श्रीमती के बयान भी दर्ज किये। मुल्ली देवी, राम दयाल, गोपाल, संजय, सीता राम, मथुरा, बाबू लाल, श्रीमती। छोटा, रामराय, रामेश्वर और

गणेश को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत (संक्षेप में "सीआर.पी.सी")।

4. इसके बाद पुलिस आरोपी नरेश की तलाश में उत्तर प्रदेश गई और उसे गांव पहाड़ी, जिला बांदा (यूपी) से पकड़ लिया और उसे बस्सी के थाना प्रभारी के सामने पेश किया, जिसने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि नरेश ने 20.01.1994 को मृतक गुली देवी के आभूषणों की बरामदगी के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत सूचना प्रदर्श पी-17 दी थी। यह भी आरोप है कि उपरोक्त सूचना के आधार पर, पीडब्लू-17 ने पैरों की एक जोड़ी चांदी की पायल, एक जोड़ी हाथ की चांदी की कंगन, एक जोड़ी चांदी की कान की बालियां और एक सोने की नाक की अंगूठी (नथ) बरामद की। रामचरण से और मेमो, एक्ज़िबिट पी-14 तैयार किया। पुनः 27.01.1994 को आरोपी नरेश ने अपराध के कथित हथियार "खुरपी" की बरामदगी के लिए पीडब्लू-21 को सूचना, प्रदर्शनी

पी-18 दी, जिसके अनुसार पीडब्लू-21 ने प्रदर्शनी के तहत आरोपी नरेश की निशानदेही पर "खुरपी" बरामद कर ली। पी-10.

5. डॉ. कैलाश नारायण (पीडब्लू-1) ने श्रीमती की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का परीक्षण किया। गुली देवी, जिसे परीक्षण में प्रदर्शनी पी-1 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। डॉक्टर के अनुसार सभी चोटें मृत्युपूर्व प्रकृति की थीं और मौत का कारण गर्दन के दबने के कारण श्वासावरोध से जुड़ा रक्तस्रावी सदमा था। सुगन चंद, तहसीलदार, बस्सी ने (पीडब्लू-13) के रूप में जांच की, आभूषणों की पहचान की और यह आरोप लगाया गया कि मृतक गुली देवी के पति रामेश्वर (पीडब्लू-14) ने मृतक - गुली देवी के गहनों की सही पहचान की। जांच पूरी होने के बाद, पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, बस्सी की अदालत में आईपीसी की धारा 302 और 394 के तहत प्रतिवादी के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिसने मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने आरोपी के खिलाफ

आईपीसी की धारा 302 और 394 के तहत आरोप तय किए, जिस पर आरोपी ने खुद को दोषी नहीं ठहराया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

6. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 21 गवाहों से पूछताछ की और कुछ दस्तावेज प्रदर्शित किए। इसके बाद आरोपी से सीआरपीसी की धारा 313 के तहत पूछताछ की गई। उसे अपने विरुद्ध विद्यमान परिस्थितियों को समझाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से। हालाँकि, आरोपी ने अपने बचाव में किसी गवाह से पूछताछ नहीं की।

7. मुकदमा पूरा होने पर, विद्वान निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 302 और 394 के तहत अपराध के लिए आरोपी/प्रतिवादी को दोषी ठहराते हुए सजा का आदेश पारित किया। दोषसिद्धि का आदेश पारित करने के बाद अभियुक्त को सजा के प्रश्न पर सुना गया और उसके बाद सत्र न्यायाधीश ने उसे आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाने का आदेश पारित किया।

8. उपरोक्त निर्णय और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर, प्रतिवादी ने राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील दायर की, जिसे डी.बी. के रूप में पंजीकृत किया गया था। सी.आर.एल. 1996 की जेल अपील संख्या 331। उपरोक्त अपील राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई।

9. रिकॉर्ड पर सबूतों की स्क्रीनिंग के बाद, उच्च न्यायालय ने माना कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था और अभियोजन का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। कथित तौर पर श्रृंखला बनाने वाली प्रत्येक परिस्थिति की उच्च न्यायालय द्वारा जांच की गई और उसकी जांच करने पर यह माना गया कि उक्त परिस्थितियों में से कोई भी यह निष्कर्ष नहीं निकालती कि प्रतिवादी ने उपरोक्त अपराध किया है। उच्च न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष द्वारा जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया, वे विसंगतियों से भरी हैं और वे इस विश्वास को प्रेरित नहीं करतीं कि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अभियुक्त ने अपराध

किया था। उच्च न्यायालय ने माना कि "*आरोपी को आखिरी बार मृतक के साथ देखा गया*" से संबंधित अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें से किसी ने भी विशेष रूप से यह नहीं कहा कि आरोपी ने मृतक का पीछा करते हुए उस खेत तक पहुंचाया, जहां घटना हुई थी। जहां तक दूसरी परिस्थिति का सवाल है, कि आरोपी को घटना के तुरंत बाद घटना स्थल से भागते हुए पाया गया था, उच्च न्यायालय ने पीडब्लू -4, 7, 8 और 9 के साक्ष्य में विसंगतियों की ओर इशारा किया है और उसी का विश्लेषण करने पर यह माना गया कि उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि मृतक को आखिरी बार आरोपियों के साथ देखा गया था या वह अपने हाथों में "लोटा" या "पोटली" लेकर घटना स्थल से भागता हुआ पाया गया था।

10. अभियोजन पक्ष द्वारा कथित तौर पर साबित की गई अन्य परिस्थिति आरोपी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर मृतक के

आभूषणों की बरामदगी का तथ्य थी। उस संबंध में, डिवीजन बेंच ने माना कि एकमात्र साक्ष्य, जिस पर उस संबंध में भरोसा किया जाता है, वह पीडब्ल्यू - 20 और 21 के साक्ष्य हैं और उसी की जांच पर उच्च न्यायालय ने माना कि प्रदर्शन पी-17 पर एक नज़र केवल यह इंगित करती है कि आरोपी ने खुशाल सिंह (पीडब्लू-21) को सूचित किया कि उसने गहने राम चंद्र सराफ, मछली बाजार, बांदा को बेच दिए हैं, जबकि गहने राम चरण (पीडब्लू-20) से बरामद किए गए थे। उच्च न्यायालय ने पीडब्लू-20 के साक्ष्य में भी विसंगति पाई, जिसने कहा है कि उसने गहने नहीं खरीदे। वह इस बात का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका कि उक्त आभूषण उसकी सुरक्षा और कब्जे में किसने छोड़े थे। उच्च न्यायालय ने यह भी बताया कि उक्त गवाह के अनुसार आरोपी ने उसी दिन गहने ले लिए, और इसलिए, पीडब्लू-20 से आरोपी द्वारा दिखाए गए गहने बरामद करने का कोई मामला नहीं हो सकता है। परिणामस्वरूप, यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह मानना सुरक्षित नहीं होगा कि आभूषणों

की बरामदगी आरोपी/नरेश द्वारा दी गई जानकारी के अनुरूप थी, खासकर, जब न तो आभूषण उसी व्यक्ति से बरामद किए गए हैं जिसके बारे में आरोपी ने सूचित किया था और न ही दुकान वही है, जिसके बारे में आरोपी ने बताया था। मामले को ध्यान में रखते हुए, यह माना गया कि गहनों की बरामदगी और उनकी पहचान निर्णायक रूप से साबित नहीं हुई है।

11. उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अगली परिस्थिति अपराध के कमीशन में इस्तेमाल किए गए कथित हथियार की बरामदगी से संबंधित है। उच्च न्यायालय ने बताया कि पुलिस द्वारा बरामद एक्ज़िबिट पी-10, जो "खुरपी" है, उस पर कोई खून के धब्बे नहीं थे। खुशाल सिंह (पीडब्लू-21) ने भी अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि प्रथम दृष्टया "खुरपी" पर कोई खून के धब्बे दिखाई नहीं दे रहे थे और इसी कारण से उन्होंने इसे फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में नहीं भेजा था। उच्च न्यायालय ने यह भी बताया कि जिस स्थान से "खुरपी" बरामद की गई थी वह एक

खुली जगह थी और सभी और विविध लोगों के लिए सुलभ थी। प्रदर्शनी पी-10 के अवलोकन से पता चलता है कि पत्थरों के ढेर के नीचे एक "खुरपी" बरामद किया गया था और "खुरपी" जंग लगी हालत में पाया गया था। एक अन्य परिस्थिति, जिस पर अभियोजन पक्ष और ट्रायल कोर्ट द्वारा भी बहुत अधिक भरोसा किया गया था, गुली के शव पर मिली कलाई घड़ी के पट्टे की बरामदगी थी। उच्च न्यायालय ने माना कि दो गवाहों कैलाश (पीडब्लू-5) और रामेश्वर (पीडब्लू-14) ने कहा है कि पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले उन्हें कलाई घड़ी का पट्टा शव के पास पड़ा हुआ मिला और उन्होंने उसे पुलिस को सौंप दिया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने सबूतों की जांच पर माना कि यह साबित करने और स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि कलाई घड़ी का उक्त पट्टा आरोपी नरेश से संबंधित है। उच्च न्यायालय ने भी उपरोक्त परिस्थिति पर विश्वास नहीं किया, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी नरेश के कब्जे से ऐसी कोई घड़ी बरामद नहीं हुई है जिससे यह

साबित हो सके कि बरामद कलाई घड़ी का पट्टा नरेश की घड़ी से संबंधित है।

12. रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आलोक में पूरी परिस्थितियों पर चर्चा करने के बाद, उच्च न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष किसी भी परिस्थिति को साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है और परिणामस्वरूप यह माना गया कि अभियोजन अभियुक्त के अपराध को साबित करने में विफल रहा है। और तदनुसार एचएलजीएच कोर्ट ने प्रतिवादी को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

13. राजस्थान राज्य ने बरी करने के उक्त आदेश से व्यथित होकर एक विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिस पर नोटिस जारी किया गया और छुट्टी दी गई। जब अपील को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था तब हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों को सुना है,

जिन्होंने बड़ी मेहनत से हमें रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से अवगत कराया है।

14. अपीलकर्ता - राजस्थान राज्य की ओर से उपस्थित वकील श्री मिलिंद कुमार ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया कि ऐसी कई परिस्थितियाँ हैं जो प्रतिवादी के अपराध को जन्म देती हैं और साबित करती हैं। पहली परिस्थिति, जिस पर भरोसा किया गया था, वह थी "आरोपी द्वारा मृतक के पीछे जाने और उसके बाद घटना स्थल से अकेले बाहर आने का अंतिम बार देखा गया तथ्य। अगली परिस्थिति, जिस पर सरकारी वकील ने भरोसा किया, वह शव पर कालिख पोतने का तथ्य है।" जब प्रतिवादी अदालत से आ रहा था तो उसने उस पर कीचड़ उछाला। दूसरी परिस्थिति जिस पर बहुत अधिक भरोसा किया गया वह रामचरण साहू (पीडब्लू-20) से आरोपी की निशानदेही पर मृतक के आभूषणों की बरामदगी का कारक था। अन्य परिस्थितियाँ जैसे कि बरामदगी शव के पास खंजर और कलाई घड़ी का पट्टा सरकारी अभियोजक द्वारा सेवा में लगाया गया था।

15. हालांकि, प्रतिवादी की ओर से पेश वकील श्रीमती के. सारदा देवी ने कहा कि चूंकि वर्तमान अपील बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील है, इसलिए इसे तब तक रद्द नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अदालत आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती। इस बात के पुख्ता और विश्वसनीय सबूत कि यह आरोपी ही है जिसने अपराध किया था। उनके द्वारा दृढ़तापूर्वक कहा गया कि यदि एक ही साक्ष्य पर दो दृष्टिकोण संभव हैं, तो अभियुक्त के पक्ष में एक को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

16. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की मदद से, हमने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की जांच की है। ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर माना कि अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित चार प्रकार के परिस्थितिजन्य साक्ष्य पेश किए हैं:

(i) आरोपी हस्तरेखा शास्त्र के माध्यम से मृतक की हथेली का परीक्षण कर रहा था और मृतक खेत की ओर चला गया।

(ii) आरोपी भी खेत की ओर चला गया।

(iii) आरोपी ने अपराध करने के बाद अपना सिर धोया और मृतक का खून खेत में पाया गया।

(iv) अभियुक्त मिट्टी से सना हुआ खेत से लौटा, उसके हाथ में "पोटली" थी, उसे गाँव से दूर जाते देखा गया, और अभियुक्त की पहचान करने पर, मृतक के आभूषण, जो उतार दिए गए थे और उसके शरीर से पैर काटकर ले गए, उन्हें जब्त कर लिया गया और इन आभूषण-वस्तुओं की पहचान की कार्यवाही की गई।

17. उपरोक्त प्रत्येक परिस्थिति की जांच ट्रायल कोर्ट द्वारा रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के आलोक में की गई और अंत में यह माना गया कि उपरोक्त परिस्थितियाँ साबित करती हैं और स्थापित करती हैं कि यह अभियुक्त था जिसने अपराध किया था। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने पाया

कि उपरोक्त में से कोई भी परिस्थिति इस निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँचती है कि केवल अभियुक्त और अभियुक्त ने ही अपराध किया था।

18. इससे पहले कि हम रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों पर चर्चा करें, हमें बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप की गुंजाइश को ध्यान में रखना चाहिए। बरी करने के आदेश में हल्के ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, भले ही अदालत का मानना है कि आरोपी पर उंगली उठाने वाले कुछ सबूत हैं। इस न्यायालय ने कई मामलों में दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप की गुंजाइश से निपटा है। दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप की गुंजाइश के संबंध में उक्त निर्णयों से निकाले जाने वाले सिद्धांत को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है और वह इस प्रकार है:

अनिल कुमार बनाम यूपी राज्य, (2004) 13 एससीसी 257, पृष्ठ 261 पर, इस अदालत ने निम्नानुसार कहा:

"12. "5. अपीलीय अदालत पर उन साक्ष्यों की समीक्षा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है जिन पर बरी करने का आदेश आधारित है। आम तौर पर, बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा क्योंकि बरी करने से आरोपी की बेगुनाही की धारणा और भी मजबूत हो जाती है। आपराधिक मामलों में न्याय प्रशासन के जाल में जो सुनहरा धागा चलता है, वह यह है कि यदि मामले में पेश किए गए सबूतों पर दो दृष्टिकोण संभव हैं, तो एक आरोपी के अपराध की ओर इशारा करता है और दूसरा उसकी बेगुनाही की ओर इशारा करता है, वह दृष्टिकोण जो है अभियुक्त के अनुकूल अपनाई जानी चाहिए। न्यायालय का सर्वोपरि विचार यह सुनिश्चित करना है कि न्याय की हत्या को रोका जाए। दोषियों को बरी करने से होने वाली न्याय की हानि किसी निर्दोष को दोषी ठहराए जाने से कम नहीं है। ऐसे मामले में जहां स्वीकार्य साक्ष्य को नजरअंदाज कर दिया जाता है, अपीलीय अदालत पर उन साक्ष्यों की फिर से सराहना

करने का कर्तव्य बनता है जहां आरोपी को बरी कर दिया गया है, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि क्या किसी आरोपी ने वास्तव में कोई अपराध किया है या नहीं। (*भगवान सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य देखें*) दोषमुक्ति के फैसले के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए अपीलीय अदालत द्वारा पालन किया जाने वाला सिद्धांत केवल तभी हस्तक्षेप करना है जब ऐसा करने के लिए बाध्यकारी और पर्याप्त कारण हों। यदि आक्षेपित निर्णय स्पष्ट रूप से अनुचित है और प्रक्रिया में प्रासंगिक और ठोस सामग्री को अनुचित तरीके से हटा दिया गया है, तो यह हस्तक्षेप का एक अनिवार्य कारण है। इस न्यायालय द्वारा *शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य, रमेश बाबूलाल दोशी बनाम गुजरात राज्य, जसवन्त सिंह बनाम हरियाणा राज्य, राज किशोर झा बनाम बिहार राज्य, पंजाब राज्य बनाम कमाल सिंह और पंजाब राज्य बनाम* में इन पहलुओं पर प्रकाश डाला गया था। फूला सिंह।”

चंद्रप्पा बनाम कामताका राज्य, (2007) 4 एससीसी 415, पृष्ठ 432 पर, इस अदालत ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

"42. ...हमारे विचार में, दोषमुक्ति के आदेश के खिलाफ अपील से निपटने के दौरान अपीलीय अदालत की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित सामान्य सिद्धांत सामने आते हैं:

(1) एक अपीलीय अदालत के पास उन सबूतों की समीक्षा, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति है, जिन पर बरी करने का आदेश आधारित है।

(2) आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 इस तरह की शक्ति के प्रयोग पर कोई सीमा, प्रतिबंध या शर्त नहीं लगाती है और अपीलीय अदालत तथ्य और कानून दोनों के प्रश्नों पर अपने निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सबूतों पर विचार कर सकती है।

(3) विभिन्न अभिव्यक्तियाँ, जैसे, "पर्याप्त और सम्मोहक कारण", "अच्छे और पर्याप्त आधार", "बहुत मजबूत परिस्थितियाँ", "विकृत निष्कर्ष", "स्पष्ट गलतियाँ", आदि का उद्देश्य किसी की व्यापक शक्तियों को कम करना नहीं है। दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में अपीलीय अदालत। इस तरह की पदावली "भाषा के उत्कर्ष" की प्रकृति में अधिक हैं, जो साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने के लिए अदालत की शक्ति को कम करने की तुलना में अपीलीय अदालत की बरी करने में हस्तक्षेप करने की अनिच्छा पर जोर देती हैं।

(4) हालाँकि, अपीलीय अदालत को यह ध्यान में रखना चाहिए कि बरी होने की स्थिति में, अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा होती है। सबसे पहले, निर्दोषता का अनुमान उसे आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत के तहत उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वह सक्षम अदालत द्वारा दोषी

साबित न हो जाए। दूसरे, आरोपी ने अपनी रिहाई सुनिश्चित कर ली है, उसकी बेगुनाही की धारणा को ट्रायल कोर्ट द्वारा और भी मजबूत, पुन: पुष्टि और मजबूत किया गया है।

(5) यदि रिकॉर्ड पर साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय अदालत को ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए दोषमुक्ति के निष्कर्ष को परेशान नहीं करना चाहिए।"

यूपी राज्य में बनाम गंभीर सिंह, (2005) 11 एससीसी 271, पृष्ठ 272 पर, इस अदालत ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

"हम बरी किए जाने के खिलाफ अपील में उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए राजी नहीं हैं। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि एक ही साक्ष्य पर दो दृष्टिकोण उचित रूप से संभव हैं, तो अभियुक्त के पक्ष में एक को प्राथमिकता दी जानी चाहिए"।

19. जब हम उपरोक्त कानूनी सिद्धांतों की पृष्ठभूमि के आलोक में वर्तमान मामले की जांच करते हैं, तो हम पाते हैं कि अभियोजन द्वारा जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया उनमें से कोई भी आरोपी के खिलाफ साबित नहीं हुई, जिससे एक निश्चित निष्कर्ष निकला कि यह आरोपी ही था, जिसने अपराध किया. साक्ष्यों से पता चला है कि मृतक दिनांक 12.08.1993 को लगभग 3 बजे खेत की ओर गया था तथा अभियुक्त नरेश भी हाथ में "लता" लेकर खेत की ओर गया था। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा बयान पुलिस के सामने नहीं दिया गया था और उच्च न्यायालय ने इसे सुधार के रूप में पाया और फैसले में दर्ज किया। मथुरा (पीडब्लू-4) ने अपने बयान में कहा है कि वह मवेशियों को चारा देने के लिए "कोठी" में गई थी। उसने यह भी कहा कि जब वह मवेशियों को पानी पिलाने के लिए खेत में बैठी थी, तो उसने देखा कि आरोपी नरेश गांव की ओर भाग रहा था और आरोपी के साथ एक "गद्दी" और एक "गांव" भी था। अपनी जिरह में, उसने कहा कि उसने आरोपी को

"खेली" पर बैठे देखा था और उसने आरोपी/नरेश की ओर पीठ कर ली थी क्योंकि आरोपी अपने हाथ धो रहा था। यदि वह गवाह घटना स्थल के निकट खेत में मौजूद होती, तो ऐसा कोई अवसर नहीं होता कि उसने कथित वास्तविक घटना को क्यों नहीं देखा होता। यदि आरोपी ने अपराध किया है तो उसे घटना स्थल पर बहुत लंबे समय तक रुकना पड़ा होगा क्योंकि आरोप है कि आरोपी ने मृतक के दोनों पैर और पैरों की एक जोड़ी चांदी की पायल, हाथों की एक जोड़ी चांदी के कंगन काट दिए थे। , चांदी की एक जोड़ी कान की बाली और एक सोने की नाक की अंगूठी (नथ) कथित तौर पर उसके द्वारा ले ली गई। जब आरोप "खुरपी" के उपयोग से दोनों पैरों को काटने का है, तो इसमें काफी समय लगा होगा, जिसके दौरान उक्त गवाह (पीडब्लू-4) ने घटना को स्वयं देखा होगा। पीडब्लू4 की ओर से इस बात का भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि जब उसने आरोपी को हाथ धोते देखा तो उसने अपनी पीठ क्यों मोड़ ली। वह यह नहीं

बताती कि उसने मृतक को आरोपी के साथ देखा था और न ही यह बताती है कि उसने आरोपी को कीचड़ से सना हुआ देखा था।

20. किसी भी गवाह की ओर से एक भी बयान नहीं आया कि उन्होंने किसी पानी को मृतक के खून से सना हुआ देखा हो या किसी खेत की मिट्टी को इंसान के खून से सना हुआ देखा हो. कुछ गवाहों ने कहा है कि जब आरोपी खेत से लौट रहा था तो उस पर कीचड़ लगा हुआ था जबकि मथुरा (पीडब्लू-4) ऐसा नहीं कहता है। वह केवल इतना कहती है कि उसने उसे खेतों से भागते हुए देखा था। यह भी ज्ञात नहीं है कि उक्त गवाह ने केवल इसलिए अभियुक्त की ओर पीठ क्यों कर ली क्योंकि अभियुक्त अपने हाथ धो रहा था। यदि अभियुक्त अपने हाथ धो रहा था, जैसा कि मथुरा (पीडब्लू-4) ने कहा था, तो आरोपी के शरीर पर कीचड़ लगे होने की कोई संभावना नहीं है, जैसा कि अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों (पीडब्लू 7 और 8) ने आरोप लगाया था।

21. विद्वान निचली अदालत ने भी आरोपी को दोषी ठहराया क्योंकि मृतक के शव के पास कलाई घड़ी का पट्टा पाया गया था, जो कथित तौर पर आरोपी का था। साक्ष्यों की जांच करने पर हमें ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला कि कलाई घड़ी का उक्त पट्टा अभियुक्त की घड़ी का है। किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा कि कलाई घड़ी का ऐसा पट्टा अभियुक्त का है और न ही अभियुक्त के पास से कोई कलाई घड़ी बरामद हुई है। जहां तक घटना के समय का सवाल है, वहां भी कोई एकमत नहीं है और घटना के समय के संबंध में साक्ष्य भी कम हैं। हमारी सुविचारित राय में, आरोपी द्वारा क्षेत्र में अपराध करने और मृतक के पैर काटने से संबंधित साक्ष्य न तो ठोस हैं और न ही विश्वसनीय हैं, और इसलिए, प्रतिवादी की सजा के आधार के लिए उन परिस्थितियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

22. जहां तक गहनों की बरामदगी की बात है तो उस संबंध में मुख्य गवाह पीडब्लू-20 है। उक्त आभूषण आरोपियों की निशानदेही पर

पीडब्लू-20 की हिरासत और कब्जे से बरामद किए गए। हमने पीडब्लू-20 के साक्ष्यों का बहुत सावधानी से विश्लेषण किया है ताकि उक्त गवाह की विश्वसनीयता का पता लगाया जा सके। उसने अपने परीक्षा प्रमुख को बताया था कि आरोपी उसके पास यह कहकर आया था कि वह अपने घर के गहने बेचना चाहता है। हालाँकि, उक्त गवाह ने कहा कि उन्होंने ऐसे आभूषण नहीं खरीदे, जिन्हें बाद में उनसे जब्त कर लिया गया। उन्होंने जिरह में बताया कि वे पुराने गहनों से नये गहने बनाने का कारोबार करते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उक्त आभूषण उनके उपयोग के लिए नहीं थे और इसलिए उन्होंने खरीदने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि नरेश/अभियुक्त स्वयं एक सुनार है इसलिए वह पहले भी उसके पास आता था। उन्होंने यह भी कहा कि नरेश ने उनसे आभूषण रखने के लिए कहा और कहा कि वह जल्द ही वापस आएंगे, और इसलिए, उन्होंने उक्त आभूषण रख लिए और उसी दिन आरोपी ने उनके आभूषण छीन लिए। यदि आरोपी ने उसी दिन आभूषण छीन लिए तो पुलिस पीडब्लू-20 की

हिरासत और कब्जे से वही आभूषण कैसे बरामद कर सकी। इसके अलावा, चूंकि उसने कहा था कि वह आभूषण नहीं खरीदेगा, इसलिए नरेश के पास उस आभूषण को पीडब्लू-20 के पास रखने का कोई अवसर नहीं था। प्रकटीकरण बयानों में आरोपी ने कहा कि उसने आभूषण राम चंद्र सराफ को बेचे थे जबकि उसे पीडब्लू-20 से बरामद किया गया था। सबूतों की जांच करने पर, हम पाते हैं कि आभूषणों की उपरोक्त बरामदगी पूरी तरह से रहस्य में डूबी हुई है क्योंकि यह उस स्थान और व्यक्ति से बरामद नहीं किया गया था जिसे कथित तौर पर आरोपियों ने बेचा था।

23. जहां तक "खुरपी" की बरामदगी का सवाल है तो माना जाता है कि उस पर कोई खून का धब्बा नहीं था और उसे एक खुले स्थान से बरामद किया गया था। चूंकि उस पर कोई खून का धब्बा नहीं था, इसलिए पुलिस ने उसे रासायनिक जांच के लिए भी नहीं भेजा. अत: यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त हथियार का प्रयोग मृतक की हत्या करने में किया गया था। घटना के समय आरोपी के आचरण के संबंध में कुछ संदेह हो सकता

है लेकिन यह किसी भी तरह से निर्णायक रूप से साबित या स्थापित नहीं हो सकता है कि आरोपी ने मृतक की हत्या की है। जब तक हम इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाते कि प्रस्तुत साक्ष्य स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से अभियुक्त के अपराध को स्थापित करते हैं, हम बरी करने के आदेश को रद्द करके दोषसिद्धि का आदेश पारित नहीं कर सकते।

24. उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण पाया गया है, और इसलिए, लाभ हमेशा अभियुक्त को जाना चाहिए, न कि अभियोजन पक्ष को। यदि अभियोजन पक्ष तथ्य को साबित करना चाहता है, तो इसे प्रमुख साक्ष्यों से साबित किया जाना चाहिए, जो विश्वसनीय और भरोसेमंद हो, जो अभियुक्त के अपराध को इंगित करता हो और निर्णायक रूप से साबित करता हो। यह ऐसा मामला नहीं है जहां हम सुरक्षित रूप से यह मान सकें कि दिए गए सबूत भरोसेमंद थे और निर्णायक रूप से यह स्थापित करते हैं कि केवल आरोपी ने ही अपराध

किया था। अपराध. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।

25. तदनुसार, हम इस अपील को खारिज करते हैं और उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित बरी करने के आदेश को बरकरार रखते हैं।

बी.बी.बी. अपील खारिज

आशीष तिवारी की देखरेख में शिखा पांडे द्वारा अनुवादित।